



:: आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor. GST Bhavan.
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,
राजकोट / Rajkot - 360 001



सत्यमेव जयते

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrappl3-cexamd@nic.in

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा :-

DIN- 20230764SX000000F68C

क	अपील / फाइल संख्या/ Appeal / File No.	मूल आदेश सं. / OIONo.	दिनांक / Date
	GAPPL/COM/STP/944/2023	202/D/2022-23	22-12-2022

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-162-2023

आदेश का दिनांक / 22.06.2023 जारी करने की तारीख / 07.07.2023
Date of Order: Date of issue:

श्रीशिवप्रतापसिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,
राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से मूलित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central
Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s. Manilal Nathabhai Saradva, Plot No. 23/Pavansut Apartment, Canal Road, Near Megha Shakti Park Society, Morbi-363641

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्राधिकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

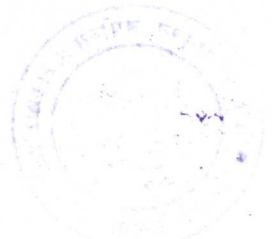
(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताया गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी मार्वाजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए।
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग, ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपा 5 लाख या उससे कम 5 लाख रुपा या 50 लाख रुपा तक अथवा 50 लाख रुपा से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति मंलग करे। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी मार्वाजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपा का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty/demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती एवं उसमें साथ जमा आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में मंलग करे (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग, ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपा 5 लाख या उससे कम 5 लाख रुपा या 50 लाख रुपा तक अथवा 50 लाख रुपा से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति मंलग करे। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी मार्वाजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपा का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assisat Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा महायुक्त आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (मेन्स्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जब केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (नं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थान अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा। /
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामला में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपूरतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौधी मंजिल, जीवन दीप भवन, समद मार्ग, नई दिल्ली- 110001, को किया जाना चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। /
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिवेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
(iv) मुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो झूठी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा ममायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। /
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के माध्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग में किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पट्टी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। /
In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रूपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in



:: अपील आदेश ::

:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Manilal Nathabhai Saradva, At Sarvad, Taluka-Maliya Miyana, Dustrict-Rajkot, Gujarat-363641 (hereinafter referred to as "Appellant") has filed present Appeal against Order-in-Original (OIO) No. 202/D/2022-23 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST, Division Morbi-I Rajkot (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

2. The facts of the case, in brief, are that Income Tax Department provided data/details of various Income Tax payers, who in their Form 26AS for financial year 2015-16 declared to have earned income by providing services classified under various service sectors. The jurisdictional Assistant Commissioner, vide letters dated 16.07.2020 and subsequent reminders called for the information/ documents. No reply/ response was received from the Appellant and in absence of any detail/information/documents from the appellant, for quantification of taxable value, no option was left but to invoke the provision of Section 72 of the Finance Act, 1994 i.e. "Best Judgement Assessment" to determine the amount to be demanded. The amount demanding the Service Tax was determined on the basis of data/ details provided by the Income Tax department and culminated into Show Cause Notice dated 30.12.2020 invoking extended period of 5 years proposing to demand Service Tax of Rs. 1,67,859/-, including all cesses under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') with interest under Section 75 of the Act, and proposing to impose penalty under Section 77(1)(a), 77(2), 77(1)(c) and Section 78 of the Act.

3. The adjudicating authority vide the impugned order confirmed Service Tax demand of Rs. 1,67,859/- under Section 73(1) invoking extended period of 5 years along with interest under Section 75 of the Act. The adjudicating authority-imposed penalties of Rs. 10,000/- under Section 77(1)(a), 77(1)(c) and Section 77(2) of the Act. The penalty of Rs. 1,67,859/- was also imposed upon the Appellant under Section 78 of the Act.

4. The Appellant has preferred the present appeal on 20.02.2023 on various grounds mainly as stated below:

The adjudicating authority has wrongly confirmed demand of Service Tax of Rs. 1,67,859/- under Section 73(1) of the Act, erred in valuation of taxable Services, erred in not allowing the benefit of Notification No. 25/2012 dated 20.06.2012, erred in demand of interest u/s 75 of the Act, erred in demanding penalty u/s 77(1)(a), 77(1)(c), 77(2) and 78 of the Act.

5. Personal hearing in the matter was held on 02.05.2023 which was attended Shri Manilal Saradva, Appellant and Shri Rajnish Adroja, Consultant, wherein he submitted that the appellant has undertaken Work Contract Service for Water Supply as sub-contractor to M/s Allwell Projects, whose name is reflected in the Form 26AS, Profit & Loss account, Balance Sheet, etc., are enclosed. After deducting this exempt income, the income from remaining Work Contract Service rendered is below threshold limit of Rs. 10 Lakhs. He requested to set aside the Order-In-Original.



6. Appellant has submitted that appellant is a sub-contractor who provides services to M/s Allwell project (Principal contractor) who provides service of installation of underground pipeline for water supply to Government of Gujarat at Morbi. Appellant has submitted that service provided by appellant is under exemption Notification No. 25/2012-ST dated 20.06.2012 at Sr. No. 12(e) read with circular No. 147/16/2011-ST dated 21.10.2011, as appellant has earned income for fitting out & installation of pipeline for water supply under Government. For the remaining amount which is below threshold limit of Rs. 10 Lakhs they are liable to pay Service Tax on it. Further, appellant submitted that in other situation value of services provided in F.Y. 2014-15 was below threshold limit and therefore they eligible for benefit of threshold limit of Rs. 10 Lakhs in successive year i.e. F.Y. 2015-16.

7. I have carefully examined the show cause notice, impugned order, appeal memorandum and written submission of the Appellant. Adjudicating authority has calculated the taxable income as Rs. 11,57,650/- this amount consists of commission income. Service Tax quantified on value of Rs. 11,57,650/- comes to Rs. 1,67,859/-. The issue to be decided in the present appeal is whether amount of Rs. 11,57,650/- reflected as taxable value in impugned order are taxable or otherwise.

7.1 From the submitted documents viz. Income Tax return, Form 26AS and invoices thereof, I observed that appellant has provided service of value amounting to Rs. 11,57,650/- to two firms, details of service provided is given hereunder:

Table - 'A'

Sr. No.	Income received from (M/s)	Income received under section of Income Tax	Amount received (Rs.)
1.	Allwell Projects	194C	9,72,650
2.	Satyam Construction	194C	1,85,000
		Total	11,57,650

7.2 From the above calculation, category of income received by the appellant is clarified. Description of sections under which income received by the appellant is given hereunder:

Table - 'B'

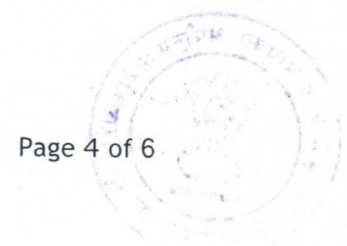
194C	<i>Tax Deduction at the Source (TDS) on sum received from contract with the sub-contractor for carrying out, or for the supply of labor for carrying out, the whole or any part of the work undertaken by the contractor or for supplying whether wholly or partly any labor which the contractor has undertaken to supply</i>
------	--

7.3 As per description of category of services provided by the appellant in pursuance of Table 'A' & 'B' above, it is seen:

i) income received under 194C is i) sum received from contract with the sub-contractor for carrying out part or whole of work or for the supply of labor.



Handwritten signature



7.4 From going through the documents viz. 26AS, work order, I find that appellant has earned income of Rs. 9,72,650/- towards supply of sub contract service to principal contractor by way of carrying out installation of pipelines for water supply which is falling under the exempt category as per Entry 12(e) of Mega Exemption Notification No. 25/2012-ST dated 20.06.2012, relevant portion of Entry No.12(e) of said Notification is reproduced hereunder:

12. Services provided to the Government, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of –

(a)

(b)

(c)

(d).....

(e) *pipeline, conduit or plant for (i) water supply (ii) water treatment, or (iii) sewerage treatment or disposal; or*

7.5 In view of above discussion and Table 'A' & 'B' given above, bifurcation of income received through service provided is given hereunder:

Table - 'C'

Particulars of Income received as	Income under Section of Income Tax	Amount involved (Rs.)	Whether taxable / exempted as per relevant Rules/Act
Contract income received by providing sub contract service to M/s Allwell Project	194C	9,72,650	Exempted as per Entry No. 12(e) of Notification No. 25/2012 dated 20.06.2012
Contract income received by providing sub contract service to M/s Satyam Construction	194C	1,85,000	Taxable
	Total	11,57,650	

7.6 Going through the documents for F.Y. 2014-15 viz. 26AS, Income Tax return, profit & loss account, I find that appellant has earned income less than threshold limit of Rs. 10 Lakhs. Therefore, benefit of threshold limit as per Notification No. 33/2012-ST dated 20.06.2012, is available to appellant in successive F.Y. i.e. in 2015-16 (relevant period).

7.7 To arrive at net taxable value and payable service Tax amount, after allowing benefit of threshold limit of Rs. 10 Lakhs, calculation is as under:

Particulars	Amount (Rs.)
Taxable value as per impugned Order	11,57,650/-
Taxable value after deducting exempted services (11,57,650 - 9,72,650 = 1,85,000)	1,85,000/-
Net taxable value after allowing threshold limit of Rs. 10 Lakhs (1,85,000 - 10,00,000 = 0)	0
Applicable Service Tax on net taxable value	0

Accordingly, as per the worksheet shown above & on the basis of relevant financial records/ documents, the taxable value for the relevant period is determined at 'Nil' and when taxable value is 'Nil' service tax liability is also 'Nil'.



(Signature)

9. In view of above discussions, I hold that the Appellant is not liable to pay service tax. I, therefore, set aside the service tax demand on this count. Since, the demand is set aside, recovery of interest under Section 75 and imposition of penalty under Section 77 and 78 are also required to be set aside and I order accordingly.

10. In view of the above discussion and findings, I set aside the impugned order and allow the appeal.

11. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

11. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested

[Handwritten Signature]

के. जी. सावलाणी / K. G. SAVLANI
अधीक्षक / Superintendent
के. व. एवं सेवा कर अपील्स, राजकोट
CGST Appeals, Rajkot

By R.P.A.D.

[Handwritten Signature]
22.6.23

(शिव प्रताप सिंह)
(Shiv Pratap Singh)
आयुक्त (अपील)
Commissioner (Appeals)

To, M/s. Manilal Nathabhai Saradva, At Sarvad, Taluka - Maliya Miyana, District - Rajkot, Gujarat-363641.	सेवा में, मे० मणीलाल नाथाभाई सरडवा, पोस्ट -सरवड़, तालुका- मालिया मियाणा, जिल्ला - राजकोट, गुजरात - 363641 ।
--	--

प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) प्रधान आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) अपर/संयुक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मण्डल मोरनी-I को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5) गार्ड फ़ाइल।

